>

Title: Need to rollback the increase in prices of fertilizers, extend adequate agriculture subsidy and loan at zero percent interest to farmers in the country.

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में जो उर्वरक के तीन गुना से अधिक दाम बढ़े हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस मूल्य वृद्धि से किसान की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। देश में किसान सरकार के इस फैसले से अत्यंत दुखी और निराश है।

दुनिया के अंदर अमेरिका अपने देश के किसानों को 180 विलियन डॉलर, चीन 1 खरब युआन, इंग्लैंड, रूस तथा जापान 37 विलियन डॉलर सीधे सब्सिडी दे रहे हैं। इसी वजह से वहां के किसानों का कृषि उत्पादन व्यय हमारे देश की तुलना में 40 से 60 प्रतिशत कम आ रहा है। किंतु भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त की जा रही है। अभी जो खाद के दाम बढ़ाए गए हैं वे निम्न प्रकार हैं ः-

डी.ए.पी. की 1 बोरी जो 527.45 रू. की मिलती थी, अब वह बोरी 1272.35 रू. हो गई है।

एन.पी.के. (12-डी 32-16) पहले 457.83 रू. की प्रति बोरी मिलती थी, अब 1132.21 रू. में मिलेगी।

एन.एन.पी.के. (20-पी.के. (10-22-26) 435.50 रू. बोरी थी, अब 1176.90 रू. में मिलेगी।

20-0.13 एक बोरी 381.75 में मिलती थी, लेकिन अब 1007.22 में मिलेगी। पोटाश 267.94 से बढ़कर 890.64 रू. कर दी गई।

इस तरह तीन गुना खादों के दाम बढ़ाए गए हैं। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। वैसे ही किसान का खेती का धंधा घाटे का है। कर्ज के बोझ से दबकर अब तक देश में 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि बढ़े हुए उर्वरकों के दाम तत्काल वापस लिए जाए तथा किसानों के फसल के समर्थन मूल्य लागत खर्च के अनुपात में तय किए जाए। देश में किसान तथा कृषि योग्य भूमि दोनों तेज गति से कम होते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। देश को यदि खाद्यान्न से आत्मनिर्भर बनाना है तो किसानों को मध्य प्रदेश की तरह शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण तथा सब्सिडी बढ़ाए जाने पर विचार करें, अन्यथा वर्ष 2020 के बाद देश को अन्न की भयंकर कमी का सामना करना पड़ सकता है।